



प्रशांत भूषण के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, नितिन नबीन बोले-बेनकाब हुआ विपक्ष का एजेंडा

नयी दिल्ली १६/१० (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के ‘सच्चा परिवर्तन’ संबंधी बयान को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा। नबीन ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने के विपक्ष के ‘दुर्भावनापूर्ण एजेंडे’ को उजागर करती है।

नवीन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि विपक्ष की लड़ाई चुनाव सुधारों, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) या देश के युवाओं के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि अराजकता फैलाकर किसी भी कीमत पर सच्चा हासिल करने के लिए है। उन्होंने कहा, “‘सच्चा परिवर्तन’ (रिजीम चेंज) जैसे शब्दों के इस्तेमाल से विपक्ष का असली एजेंडा देश के सामने



स्पष्ट रूप से उजागर हो गया है। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने का यह कुत्सित प्रयास ‘अर्बन नरसल’ के एजेंडे का ही हिस्सा है।”

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में सच्चा का मार्ग जनता से होकर गुजरता है, अराजकता से नहीं। उन्होंने कहा कि देश की जनता और भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच प्रशांत भूषण ने बृहस्पतिवार को ‘सच्चा परिवर्तन’ का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करना लोकतंत्र में अपराध नहीं है और यह हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है।

भूषण ने यहां कॉकरोच जनता पार्टी (काँजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके, छात्र संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि फिलहाल उनका संघर्ष निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन यदि इसी

तरह की बर्बरता जारी रही तो सच्चा परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। भूषण की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी समेत भाजपा के कई नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और लोगों से गुस्सा भड़काने के कथित प्रयासों के झांसे में नहीं आने की अपील की। जोशी ने ‘एक्स’ पर कहा कि जिस तरह की बाहरी साजिशों ने लीबिया, नेपाल और बांग्लादेश को अस्थिर किया, वैसी ही कोशिश भारत की शांति भंग करने के लिए की जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के गुस्से का इस्तेमाल अराजकता फैलाने और देश की विकास यात्रा को रोकने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से राजनीतिक साजिशों का हिस्सा बनने से बचने और स्थिरता तथा राष्ट्रीय प्रगति के साथ खड़े रहने की अपील की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने भूषण के संवाददाता सम्मेलन का वीडियो साझा करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा,

“इन चेहरों को पहचानिए।” उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से हासिल करने में असफल राष्ट्रविरोधी ताकतें अब सड़कों के माध्यम से सच्चा परिवर्तन की कोशिश कर रही हैं। शर्मा ने कहा कि देश के लोग मिलकर इन ताकतों का मुकाबला करेंगे और उनकी कथित राष्ट्रविरोधी योजनाओं का जवाब देंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ‘एक्स’ पर कहा कि ‘सच्चा परिवर्तन’ शब्द का इस्तेमाल विदेशी तत्वों द्वारा अपने हितों के लिए निर्वाचित सरकारों को गिराने के प्रयासों के संदर्भ में किया जाता है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि युवाओं को समझना चाहिए कि कुछ महीने पहले परीक्षा प्रणाली और प्रवेश परीक्षाओं में सुधार की मांग के साथ शुरू हुआ आंदोलन अब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कथित साजिश का हिस्सा बन गया है।

राज्य में आठ साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव, एबीवीपी ने सात और बीसीजेडी ने चार विश्वविद्यालय जीते

भुवनेश्वर १६/१० (संवाददाता): ओडिशा के छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे प्रमुख ताकत बनकर उभरी है। राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में से 7 पर ABVP ने जीत हासिल की है, जिसमें उत्कल विश्वविद्यालय भी शामिल है। आठ वर्षों में पहली बार हुए इन कैंपस चुनावों में, BJD के छात्र संगठन बीजू छात्र जनता दल ने 4 विश्वविद्यालयों में जीत दर्ज की है। बाकी दो विश्वविद्यालयों में नतीजे मिले-जुले रहे, जबकि मतदान का प्रतिशत कम रहा; बरहमपुर विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में तो मतदान 10% से भी कम दर्ज किया गया। इसको लेकर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के एक्स पर लिखा कि ओडिशा में संपन्न छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शानदार जीत पर सभी विजयी प्रत्याशियों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। यह जीत युवाओं के नाम पर अराजकता



फैलाने की राजनीति को नकारते हुए राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के प्रति युवा शक्ति के अटूट विश्वास को दर्शाती है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रेरित भारत का युवा आज राष्ट्रनिर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार को हुए चुनावों में जबरदस्त प्रचार देखने को मिला और पहली बार वोट डालने वाले छात्रों को लामबंद किया गया। परिसरों (कैंपसों) में ABVP और BCJD के बीच कड़ी टक्कर रही। इस दौरान झड़पें भी हुईं, धांधली के आरोप लगे और यह भी कहा गया कि राज्य सरकार

ने ABVP के उज्ज्मीदवारों का पक्ष लिया। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, 325 कॉलेजों और 13 राज्य विश्वविद्यालयों में 6,649 उज्ज्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ABVP ने चुनाव वाले 325 कॉलेजों में से 60% से ज्यादा में जीत का दावा किया है, हालांकि सभी कॉलेजों के अंतिम नतीजे तुरंत उपलब्ध नहीं हो सके। राज्य के सबसे पुराने विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय में, ABVP ने नौ में से सात पदों पर जीत हासिल की। जिनमें अध्यक्ष और महासचिव के पद शामिल हैं। कांग्रेस से जुड़ी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने उपाध्यक्ष और संयुक्त महासचिव के पद जीते।

परिसीमन प्रस्तावों पर पीएम नरेन्द्र मोदी को मल्लिकार्जुन खरगे का पत्र, सर्वदलीय बैठक की मांग

नयी दिल्ली १६/१० (संवाददाता): कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चौथा पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने परिसीमन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और संसद में पेश करने से पहले, इन पर चर्चा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। शुक्रवार को भेजे गए इस पत्र में, खड़गे ने प्रक्रियात्मक और संवैधानिक चिंताएं जताई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 13 अगस्त को मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से अब तक 64 दिनों का एक अभूतपूर्व अंतराल हो चुका है, जबकि सत्र का औपचारिक सत्रावसान भी नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि वह आम



सहमति के बिना कोई भी बड़ा संवैधानिक संशोधन न थोपे। खरगे ने कहा कि 13 अगस्त 2026 को संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित (एडजॉर्न साइन डाई) हुए 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान (प्रोरोगेशन) अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने समझाया कि %अनिश्चित काल के लिए स्थगन% का

मतलब है कि सत्र को बिना किसी अगली तारीख के रोक दिया गया है, जबकि सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक %सत्रावसान% आदेश की आवश्यकता होती है। खरगे ने तर्क दिया कि दोनों सदनों के सत्रावसान में दो महीने से अधिक की देरी से यह अटकलें लग रही हैं कि संसद को अचानक फिर से बुलाया जा सकता है या सत्र

को बढ़ाया जा सकता है, जिससे सांसदों के लिए तय %नोटिस अवधि% (सूचना देने का समय) को दरकिनार किया जा सकता है। खरगे ने एक घटनाक्रम पेश करते हुए बताया कि कैसे सरकार अपनी मर्जी से फैसले थोप रही है। उन्होंने याद दिलाया कि अप्रैल में सरकार ने बहुत कम समय का नोटिस देकर %परिसीमन संवैधानिक संशोधन विधेयक% पेश किया था, जो 17 अप्रैल को लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत न जुटा पाने के कारण गिर गया। उन्होंने लिखा कि आपको याद होगा कि मैंने 11 अप्रैल 2026 को आपको पत्र लिखकर कहा था कि परिसीमन से जुड़ा कोई भी संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने से पहले सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए।

नयी दिल्ली १६/१० (संवाददाता): अपनी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर हो रहे भारी विरोध के बीच, चुनाव आयोग ने दो ऐसे मुद्दों पर अपना रुख बदल दिया है, जिन पर लंबे समय से विपक्ष के साथ उसका टकराव चल रहा था। पिछले 24 घंटों में, दबाव का सामना कर रहे चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए %स्पेशल समरी रिवीजन% (स्क्र) की घोषणा की है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने पहली बार राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की ऐसी PDF कॉपी देने का वादा किया है जिसे आसानी से पढ़ा जा सके – जो कि उसके अपने ही पुराने रुख से एक बड़ा बदलाव है। हाल के वर्षों में विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने इन दोनों



मुद्दों को बार-बार उठाया है। दूसरे ऐलान ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब खुद चुनाव आयोग ने निजता से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए मशीन से पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची जारी करने का विरोध किया था। यह समय काफी अहम है। %कॉकरोच जनता पार्टी% और विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-

प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। आरोप है कि मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) में गड़बड़ियां की गई हैं। पूरे देश में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया के चलते 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं, जिससे भारी अफरा-तफरी मच गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रुक्चर के कारण, चुनाव आयोग ने विशेष स्कूरप्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके जरिए नए पात्र मतदाताओं (जिनमें 18 वर्ष के होने वाले लोग भी शामिल हैं)

दिल्ली में तिरंगा मार्च निकाल रहे करीब १५० प्रदर्शनकारी हिरासत में, कर्नाटप्लेस में सुरक्षा कड़ी

नयी दिल्ली १६/१० (संवाददाता): हाथों में तिरंगा लेकर और ‘जय हिंद’ के नारे लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (काँजपा) के सैकड़ों समर्थकों और छात्र संगठनों के सदस्यों ने शुक्रवार शाम मध्य दिल्ली में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए। पुलिस ने कर्नाट प्लेस में पार्टी के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च की अनुमति नहीं दी थी। काँजपा के संस्थापक अभिजीत दीपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा सहित करीब 150 प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इन हिरासतों को लेकर विपक्ष ने तीखी आलोचना की, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रदर्शन को युवाओं का

इस्तेमाल कर ‘अराजकता’ फैलाने और सच्चा परिवर्तन की कोशिश करार दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लेने के बाद दीपके को जाफरपुर कलां थाने ले जाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कर्नाट प्लेस के इनर सर्कल में मार्च किया। वे बीच-बीच में ‘जय हिंद’ के नारे लगाते रहे। इसके बाद वे अलग-अलग स्थानों पर तितर-बितर हुए और फिर एकत्र हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान भी गाया। छात्रों और आइसा व एसएफआई के सदस्यों ने मंडी हाउस में प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वापस लेने और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अधिनियम को वापस लेने की

मांग की। सांसद जॉन ब्रिटान और संतोष कुमार सहित वामपंथी नेताओं ने डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस मार्च में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिशों के दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच मामूली झड़पें भी हुईं। प्रदर्शनों की कवरज के लिए पत्रकार और स्वतंत्र यूट्यूब रिपोर्टर भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान कुछ स्वतंत्र यूट्यूब पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की और हट्टिंग की गई। दिल्ली पुलिस ने दीपके और बोरा को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाते समय एहतियातन हिरासत में ले लिया। काँजपा नेता कर्नाट प्लेस जा रहे थे, जबकि आइसा अध्यक्ष मंडी हाउस जा रही थीं। दीपके को झंडेवाला न स्थित



उनके आवास से हिरासत में लिया गया, जबकि बोरा को मंडी हाउस में हिरासत में लिया गया। इन हिरासतों के दौरान वहां मौजूद भीड़ और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। पुलिस ने कर्नाट प्लेस पहुंच चुके प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लेना शुरू कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को

हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों में मुंबई के डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय का 21 वर्षीय छात्र तक्ष भी शामिल था। उसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और एक तख्ता ले रखी थी, जिस पर लिखा था, ज्ञानेश कुमार जल्दी इस्तीफा दो, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। उसने बताया कि वह प्रदर्शन में

शामिल होने के लिए एक महीने से दिल्ली में है और विश्वविद्यालय की कक्षाओं में ऑनलाइन शामिल हो रहा है। तक्ष ने कहा, मैंने दो हजार रुपये में लाल लहंगा खरीदा है। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर लिखा था, एसआईआर बंद करो, वोट चोरी बंद करो, मेरा वोट किसने हटायो? और पुलिस की हिंसा कोई दुर्घटना नहीं है। इससे पहले दिन में दिल्ली पुलिस के 20 से अधिक कर्मी दीपके के आवास पर पहुंचे थे और उन्हें एक नोटिस दिया था। नोटिस में उन्हें ऐसी किसी भी कार्रवाई से दूर रहने का निर्देश दिया गया था, जिससे नागरिकों, व्यापारियों, यात्रियों, मरीजों और अन्य लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने

राष्ट्रपति भवन के पास और मध्य दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय के बाहर तिरंगा मार्च निकाला। पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पंडित रविशंकर शुक्ला लेन स्थित कार्यालय के बाहर तिरंगा लेकर मार्च किया और ‘भारत माता की जय’ तथा ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाए। प्रदर्शनों की केंद्र सरकार ने तीखी आलोचना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर बांग्लादेश की तर्ज पर सच्चा परिवर्तन की कोशिश करने तथा युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल ‘अराजकता’ फैलाने के लिए करने का आरोप लगाया। लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि लोकतंत्र किसी को भी अव्यवस्था फैलाने या संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करने

की अनुमति नहीं देता। रक्षा मंत्री ने कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके राजनीतिक सहयोगी, सीधे तौर पर और अपने सहयोगी संगठनों के माध्यम से, युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल राजनीतिक टकराव बढ़ाने और अराजकता फैलाने के लिए करना चाहते हैं। वे इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने के बजाय ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देश के युवाओं को अराजकता की राजनीति में मोहरा बनाया जा रहा है। सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सरकार बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, वे संवाददाता सम्मेलनों में खुले तौर पर कहते हैं कि उन्होंने सच्चा परिवर्तन के लिए बांग्लादेश से प्रेरणा ली है।



भारत को घुसपैठिया मुक्त बनाने के लिए अमित शाह का एज्शन तेज, घुसपैठियों के बारे में सूचना देने के लिए पोर्टल शुरू

नयी दिल्ली १६/१० (संवाददाता): केंद्र की मोदी सरकार देश से घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अब इस मुहिम में आम नागरिक भी सरकार की मदद कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए विशेष पोर्टल शुरू किया है, जहां अवैध घुसपैठ और सांझिक बसावट से जुड़ी जानकारी सझा की जा सकती है।यानी अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति के अवैध रूप से भारत में रहने की विश्वसनीय जानकारी है, तो आप सरकार को इसकी सूचना दे सकते हैं। मोदी सरकार को इस पहल का मकसद घुसपैठियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष सेवानिवृज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर ने नई दिल्ली में विशेष पोर्टल https://demography.mha.gov.in लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए केंद्र और राज्य सरकारें, संस्थाएं तथा आम नागरिक

संदिग्ध बसावट और जनसांज्यिकीय बदलावों से जुड़ी जानकारी सझा कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य अवैध अप्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए ऐसी स्थायी व्यवस्था तैयार करना है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत तेजी और प्रभावी ढंग से काम करे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों और आम नागरिकों के लिए खुला है। यहां उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारीयों के आधार पर समिति अवैध अप्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक स्थायी, व्यवस्थित, कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध व्यवस्था बनाने की सिफारिश करेगी। यानी अब जोर केवल समस्या की पहचान पर नहीं, बल्कि उससे निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार करने पर भी है। हम आपको याद दिला दें कि इस समिति का गठन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 मई 2026 को किया था। इसकी

पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, समिति को देश में अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले असामान्य जनसांज्यिकीय बदलावों का व्यापक अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके दायरे में प्रजनन दर में अंतर, सीमा पार आवागमन, आर्थिक अवसरों, सामाजिक-पर्यावरणीय परिस्थितियों और असामान्य बसावट के पैटर्न जैसे पहलू शामिल हैं।

समिति का काम केवल आंकड़े इकट्ठा करना नहीं है। उसे यह भी देखना है कि किन क्षेत्रों में जनसंज्या का स्वरूप बदल रहा है, इन परिवर्तनों के पीछे कौन-से कारक हैं और सीमा प्रबंधन तथा पहचान प्रणालियों को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है। धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंज्या संबंधी बदलावों का अध्ययन भी उसके कार्यक्षेत्र में रखा गया है।देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीतिगत



प्राथमिकताओं में अवैध घुसपैठ का मुद्दा लगातार प्रमुखता से उभरा है। मई 2026 में उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के दौरान शाह ने अवैध घुसपैठ से पैदा होने वाले जनसांज्यिकीय बदलावों को देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बताया था। गृह मंत्रालय के अनुसार, समिति को अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर देनी है; जरूरत पड़ने पर इसका कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। हम आपको याद दिला दें कि अगस्त 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सज्मेलेन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भारत को कम समय में घुसपैठिया मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया था। इससे पहले फरवरी 2026 में दिल्ली

प्रवेश की रोकथाम, देश के भीतर पहचान का सत्यापन और निर्वासन की प्रक्रिया अलग-अलग प्रशासनिक चुनौतियां हैं। इनके प्रभावी समाधान के लिए केंद्रीय एजेंसियों, राज्य पुलिस, स्थानीय प्रशासन और संबंधित संस्थाओं के बीच तालमेल आवश्यक होगा। देखा जाये तो नया पोर्टल इस प्रक्रिया में सूचनाओं के संग्रह और विश्लेषण का माध्यम बन सकता है।

14 अज्टूबर को पोर्टल के शुभारंभ के साथ मोदी सरकार ने इस विषय पर संस्थागत स्तर पर जानकारी जुटाने का नया रास्ता खोला है। अब देखना होगा कि राज्यों और नागरिकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समिति ज्वा निष्कर्ष निकालती है और अवैध घुसपैठ की पहचान तथा निर्वासन के लिए किस प्रकार की स्थायी व्यवस्था प्रस्तावित करती है। सेवाखोजें

वैसे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या आबादी से जुड़ा सवाल अब केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रह गया है। असम से झारखंड और पश्चिम बंगाल से

लेकर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों तथा छोटे कस्बों तक अवैध प्रवास और संदिग्ध पहचान के मामलों की जांच सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम चुनौती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान भाजपा लगातार आरोप लगाती रही कि तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीतियों और वोट-बैंक राजनीति ने घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाने के प्रयासों को कमजोर किया, जबकि अमित शाह ने भी राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया था। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ समय पहले देश के सीमाई क्षेत्रों का दौरा कर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निगरानी और मजबूत करने के निर्देश दिए थे। मोदी सरकार की स्मार्ट बॉर्डर योजना के तहत निगरानी तकनीक, सीमा सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने, अवैध घुसपैठ

रोकने और लंबित सीमा-संबंधी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया था। साफ है कि सरकार का जोर केवल घुसपैठ के बाद कार्रवाई करने पर नहीं, बल्कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ के रास्तों को ही बंद करने पर है। बहरहाल, मोदी सरकार ने ‘घुसपैठिया मुक्त भारत’ के लक्ष्य की ओर अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। घुसपैठ पर लगाम कसने से लेकर अवैध रूप से देश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके निर्वासन की व्यवस्था मजबूत करने तक, सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अब इस मुहिम में नागरिकों की भागीदारी भी अहम होगी। यदि आपके पास अवैध घुसपैठ से जुड़ी कोई विश्वसनीय जानकारी है, तो उसे सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर सझा करें। देश की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प का विषय है। सरकार की सज्ती, नागरिकों की सतर्कता और कानून के प्रभावी पालन का तालमेल ही इस अभियान को मजबूती दे सकता है।

प्रशांत भूषण के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर बोली भाजपा- यह देश किसी की जागीर नहीं सौरव दास और आशुतोष रांका को ज्यों भेजा गया तिहाड़? दिल्ली पुलिस ने बताई असली वजह

नयी दिल्ली १६/१० (संवाददाता): बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को वकील प्रशांत भूषण और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने %सजा परिवर्तन% की मांग को लेकर उन पर आरोप लगाया कि उनके ये बयान चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश की ओर इशारा करते हैं।

पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्ष का अभियान केवल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण तक सीमित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और अन्य लोग राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उन पर %तत्कालपटल% करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि यह देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और न ही यह किसी एक ईंसान या एक परिवार का है। यह देश इसके 1.4 अरब लोगों का है। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण

ने कहा कि यह संघर्ष सजा परिवर्तन के लिए है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं यह देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यह किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। यह 1.4 अरब लोगों का देश है। जब वे कहते हैं कि वे सजा परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, तो इससे वही बात साबित होती है जो भारतीय जनता पार्टी और देश के आम नागरिक हमेशा से कहते आए हैं- राहुल गांधी और उनके साथियों का असली मकसद स्फ़ुर्क(एसआईआर) मुद्दे से जुड़ा नहीं है, और न ही वे हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य सजा परिवर्तन करना, सजा पर कज्जा करना और किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बनाना है—बिना चुनाव लड़े या बिना कोई मेहनत किए—ज्योंकि जनता बार-बार उन्हें नकारती रही है। हमारा संविधान सरकार बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया तय करता है। पात्रा ने कहा कि



इस देश में हर पांच साल में चुनाव होते हैं, जहां लोग अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। सजा में बदलाव के लिए यही वैध तरीके हैं।

लेकिन आप इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते। आप अराजकता और अव्यवस्था में विश्वास करते हैं। आज, प्रशांत भूषण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर यह बात स्वीकार कर ली है। यह स्पष्ट है और माना भी जा चुका है कि यह मानसिकता—चाहे वह राहुल गांधी की हो, प्रशांत भूषण की हो, या उनके पूरे समूह की—

एक खास तरह की सोच को दर्शाती है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि वे अपने खुद के नेता को भी नहीं बदल पाए हैं। जब से राहुल गांधी उनके नेता बने हैं, तब से वे एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों तक, कांग्रेस सालों से सजा से बाहर है। वे अपने नेता को तो बदल नहीं सकते, लेकिन सजा परिवर्तन करने निकल पड़े हैं। यही राहुल गांधी और गांधी परिवार की सच्चाई है। इन गद्दारों ने खुद को विदेशी ताकतों के हाथों बेच दिया है।पात्रा की ये टिप्पणियां भूषण की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आईं। भूषण ने सरकार बदलने की मांग का बचाव करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसी मांग करना जायज है। गुरुवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भूषण ने कहा कि नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार बदलने की मांग करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि

सजा परिवर्तन तो जरूर होगा। हम सभी सजा परिवर्तन चाहते हैं। ज्वा इसमें कुछ गलत है? भूषण ने यह भी सवाल उठाया कि बीजेपी सजा परिवर्तन की मांग पर आपत्ति ज्यों जता रही है, जबकि पार्टी ने खुद भी अतीत में सरकारों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सजा परिवर्तन के लिए कई बार विरोध-प्रदर्शन किए हैं, और अब वे कह रहे हैं कि सजा परिवर्तन के लिए साजिश रची जा रही है।

भूषण ने आगे तर्क दिया कि केवल सरकार बदलने की मांग करना कोई अपराध नहीं माना जा सकता।

राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना तब तक अपराध नहीं है, जब तक कि उसमें हिंसा शामिल न हो या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश न की गई हो।

न्यायपालिका को कोई दबाव नहीं डाल सकता, सीजेआई सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी से राहुल गांधी की राजनीति शैली पर उठे सवाल

नयी दिल्ली १६/१० (संवाददाता): लोकतंत्र में विरोध करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कितनी जायज है? यह सवाल इसलिए उठा है ज्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की राजनीतिक शैली पर एक तरह से गंभीर टिप्पणी कर दी है। 12 अज्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर विपक्षी नेताओं के मार्च निकाले जाने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की राजनीतिक शैली पर एक तरह से गंभीर टिप्पणी कर दी है। 12 अज्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर विपक्षी नेताओं के मार्च निकाले जाने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने दोटूक कहा, ‘न्यायपालिका को कोई दबाव में नहीं डाल सकता।' देखा जाये तो यह टिप्पणी सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि उन राजनीतिक तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाती है, जिनमें अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। यहां सवाल उठता है कि ज्वा राहुल गांधी और विपक्ष के नेता

लोकतांत्रिक विरोध की सीमा और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के बीच का अंतर भूलते जा रहे हैं? हम आपको बता दें कि 12 अज्टूबर को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं तथा समर्थकों के सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने के मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने न्यायिक परिसरों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। योजनाएंखोजें

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने

करीब 200 वकीलों के उस ज्ञापन का उल्लेख किया, जिसमें न्यायपालिका को कथित तौर पर दबाव में लेने की कोशिशों पर चिंता जताई गई थी। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने बेहद स्पष्ट शज्दों में कहा, ‘ये हल्की-फुल्की बातें हैं’ और न्यायपालिका को कोई दबाव में नहीं डाल सकता।' जब भाटिया ने अदालत के बाहर नेताओं के बयानों और न्यायिक परिसर की मर्यादा का सवाल उठाया, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हम हाथीदांत के मीनारों में नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि वे बाहर ज्वा बयान देते हैं और अदालत में ज्वा कहते हैं। हमें सब कुछ पता है।’

प्रधान न्यायाधीश के इन शज्दों को महज एक अदालती टिप्पणी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह उन राजनीतिक तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल है, जिनमें संस्थाओं के फैसले अनुकूल हों तो उनकी विश्वसनीयता का गुणगान किया जाता है और



प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हीं संस्थाओं को सार्वजनिक दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल इसलिए भी उठता है ज्योंकि निर्वाचन आयोग के कामकाज और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर अपनी आपत्तियां रखने के लिए उन्होंने जिस रास्ते का सहारा लिया, उसने विरोध और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के बीच की सीमा पर बहस छेड़ दी है।

हम आपको याद दिला दें कि विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज

को लेकर अपनी शिकायतें रखने के लिए प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात का समय मांगा था। प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें उचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी शिकायतें उठाने का रास्ता सुझाया। इसके बाद 12 अज्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च और न्यायालय की रजिस्ट्री में याचिका दाखिल करने की घटनाओं ने विवाद को और गहरा कर दिया। सवाल यह है कि जब संविधान और कानून शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं उपलब्ध कराते हैं, तब राजनीतिक लामबंदी के जरिए न्यायपालिका तक अपनी बात

पहुंचाने का दबाव बनाने की जरूरत ज्यों पड़ती है? साथ ही विवाद केवल मार्च तक सीमित नहीं है। याचिका में कांग्रेस की केरल इकाई के एक्स पोस्ट का भी उल्लेख है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश को उनके नाम से संबोधित करते हुए कहा गया था कि यदि कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वे इस्तीफा दे दें और पार्टी उनका विकल्प खोज लेगी। यह पोस्ट बाद में हटा दी गई। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की एक पोस्ट का भी याचिका में उल्लेख किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने इन बयानों को न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताते हुए न्यायिक परिसरों में राजनीतिक प्रदर्शनों पर रोक और संबंधित पक्षों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने फिलहाल इस मांग पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

देखा जाये तो संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के वल न्यायाधीशों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों के न्याय पाने के अधिकार की बुनियादी शर्त है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी संवैधानिक प्रावधानों से बंधी है; किसी राजनीतिक दल की नाराजगी या सार्वजनिक अभियान से नहीं। ऐसे में किसी मौजूदा प्रधान न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग और उनकी जगह विकल्प खोजने जैसी भाषा राजनीतिक आलोचना की सामान्य सीमा से आगे जाती दिखाई देती है।

हम आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 12 अज्टूबर को घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है। इससे साफ है कि मामले के तथ्यों और घटनाक्रम की पड़ताल आगे होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी अवमानना की

कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद ही आगे का रास्ता तय होगा। बहरहाल, राहुल गांधी और विपक्षी दलों को यह बताना होगा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना और उन पर दबाव बनाने की कोशिश करना, ज्वा दोनों एक ही बात हैं? लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सबको है, लेकिन इसके नाम पर संस्थाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाना सही नहीं उहराया जा सकता। चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट, हर संस्था के फैसलों को चुनौती देने के लिए संवैधानिक रास्ते मौजूद हैं। देखा जाये तो प्रधान न्यायाधीश का संदेश साफ है कि न्यायपालिका किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेगी और न ही किसी दल की मज्जी से चलेगी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी और उनके साथी इस संदेश से सबक लेते हैं या फिर टकराव की राजनीति को ही आगे बढ़ाते हैं।



विविध समाचार



हाथ ऊपर ले जाने पर हो दर्द तो हो सकता है रोटेटर कफ



कंधे से जुड़ी रोटेटर कफ की परेशानी ज्यादातर टेनिस, फुटबॉल प्लेयर, स्वीमर और पहलवानों को हो सकती है। गंभीर डाइस्कोट्रीज के मरीजों में भी इसके मामले देखे जाते हैं। रोटेटर कफ कंधों के जोड़ों का अधिक प्रयोग वाली चार मांसपेशियों (सुपरास्पिनेटस, इन्फ्रैस्पिनेटस, टेरैस माइनर और सक्सकैपुलरिस) के क्षतिग्रस्त होने पर होती है। जाने कारण व इलाज-
कारण- खेल के दौरान गोल करते हुए जोड़ों में खिंचाव, कंधे के बल गिरना, हाथ का गलत दिशा में मुड़ना, अधिक वजन उठाने समय कंधे पर दबाव मुख्य कारण हैं। इस दौरान अचानक खिंचाव से कंधे की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे व्यवसाय जिनमें कंधे के जोड़ों का अधिक प्रयोग हो जैसे पेंटर को भी यह समस्या होती है। डायाबिटीज के मरीजों में अक्सर मांसपेशियों में सुजन या दर्द की समस्या रहती है। जिससे इनकी मसलस में हल्का खिंचाव भी परेशानी को बढ़ाता है।
लक्षण- हाथ को ऊपर या पीछे लेने पर तेज दर्द, सुजन, खेते समय कनवट लेने पर दर्द मुख्य लक्षण हैं। दिनचर्या से जुड़े काम जिसमें कंधे के जोड़ों का मूहमेट जरूरी है, करते



समय दर्द होना।
इलाज- पेन मैनेजमेंट दर्द व सुजन कम करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं या स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं। यदि प्लेयर के पास इलाज के लिए 30 दिन से कम का समय है तो स्टेरॉयड इंजेक्शन के बजाय पेनकिलर देते हैं। ऐसे में इस इंजेक्शन से खिलाड़ी का डॉपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है।
सावधानी- कंधे से व्यायाम करते रहें खिलाड़ी या कंधे के जोड़ों का अधिक प्रयोग करने वाले लगातार काम न करें। कोशिश करें कि हर दो घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक लें। कंधे से जुड़े व्यायाम रेगुलर करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इस इजरी में फायदेमंद है। अचानक दर्द होने पर कपड़े में बर्फ रखकर प्रभावित हिस्से की 10-15 मिनट तक बर्फपाई करें।
सर्जरी- एंथ्रोस्कोपी कंधे के जोड़ों में पांच माह से लगातार दर्द हो तो क्षतिग्रस्त मसलस व दर्द की स्थिति के अनुसार एंथ्रोस्कोपी करते हैं। जिसमें मसलस के प्रभावित हिस्से को रिपेयर करते हैं। इसके बाद करीब 20-22 दिन मरीज को देखरेख में रखकर कुछ व्यायाम कराते हैं व दवाएं देते हैं।
ट्रेनर- ज्यादातर मामलों का फिजिकल थेरेपिस्ट कर लक्षणों के अधार पर इलाज करते हैं। इसके अलावा मसक्युलर स्केलेटल अल्ट्रासाउंड और एमआरआई से क्षतिग्रस्त मांसपेशी का पता लगाने में मदद मिलती है।
एक्सरसाइज- दर्द कम होने के बाद मसलस स्ट्रेचिंग व स्ट्रेन्थनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। इजरी से जो मांसपेशी जुड़ी है उसके अनुसार व्यायाम कराते हैं। इससे क्षतिग्रस्त मांसपेशी रिपेयर होती है।



कान की सफाई जरूरी होती है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि आप कैसे उसको साफ करते हैं। अक्सर घरों में सलाई में रुई लगाकर या हेयर पिन से कान साफ करते रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इससेस कानों को नुकसान पहुंचता है। आजकल आज कल सैलून और व्यूटी पार्लर में ईयर कैंडलिंग का काफी चलन में है। इसका प्रयोग कान का मैल निकालने के लिए किया जाता रहा है। प्राचीन ईजिप्ट में ईयर कैंडलिंग की प्रक्रिया बहुत पापुलर रही है। हालांकि इसे भी सुरक्षित नहीं माना जाता है।

क्या होती है ईयर कैंडलिंग
कानों की मैल को दूर करने के लिए ईयर कैंडलिंग का तरीका लंबे समय से अपनाया जा रहा है। इस नुस्खे के तहत टिगु से कान को कवर करके मोमबत्ती जलाई जाती है। इसमें मोमबत्ती का एक कोना कान के भीतर होता है और दूसरे पर चिंगारी रहती है। इसमें नीचे की तरफ भाग आती है जो सीधे कान में जाती है। जिससे कान का मैल गर्म होकर पिघल जाता है। यह उपाय से

कानों के लिए खतरा बन सकती है ईयर कैंडलिंग

लोग अक्सर अपनाते हैं जिनके कान में खुजली या जलन रहती है।
ये होते हैं नुकसान
मोमबत्ती के सिरे पर लगी आग की वजह से यह प्रक्रिया काफी खतरनाक साबित हो सकती है। कान में मोमबत्ती जलाकर मोम डालने से भी मैल नहीं निकलेगी। इससे कान जाम हो सकते हैं या फिर संक्रमण का खतरा रहता है। एकदोए इस मामले में चेतावनी देती है कि ऐसा करने से न केवल कान की नली बंद हो सकती है धरन कान का पर्दा भी फट सकता है। इससे त्वचा के अन्य अंगों के जल जाने का खतरा भी रहता है। अगर कान की मैल को हटाना चाहते हैं तो गर्म पानी से ऊपर-ऊपर साफ करें और अपने कानों को साँवर में कभी कभी रखें। इस तरीके से कान में जमा कड़ी से कड़ी मैल को गर्म किया जा सकता है और उसे छेला बनसा जा सकता है। कान की मैल साफ करने की कोशिश अच्छी होने की बजाय बुरी साबित होती है। अगर मैल को निकालने के दौरान कान की नली में और गहरे धकेल दिया जाता है तो यह नुकसानदेह होती है।

स्टेम सेल जैल से जुड़ेंगी टूटी हड्डियां

स्टेम सेल तकनीक दुर्घटनाग्रस्त अगर किसी की हड्डी टूट जाए, तो उसे जुड़ने में न सिर्फ काफी वक्त लगता है, बल्कि वह पहले जितनी मजबूत भी नहीं हो पाती है। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हड्डी में आघात दरार को भरने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से लैस एक ऐसा जैल बनाया है, जो हड्डी में आई दरार को भरने में सक्षम होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैल में मौजूद स्टेम कोशिकाओं की सहाय पर थैलर सूक्ष्म चुंबकीय कण जोड़े गए हैं। इंजेक्शन के जरिए जब इस जैल को हड्डी में पहुंचाया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर चुंबकीय गुणों से लैस पट्टी बांध दी जाती है। पट्टी के बांधने के साथ ही चुंबकीय कण सक्रिय हो जाते हैं। और हड्डियों में आई दरार को भरने में स्टेम सेल मदद करते हैं। यह परिस्थिति बहुत हद तक वैसी ही होती है, जैसी बच्चों में कार्टिलेज और हड्डियों के विकास के दौरान देखी जाती है। शोधकर्ताओं ने



परीक्षण के स्तर पर इस जैल के खरा उतरने का दावा किया है। उनकी मानें तो इसकी मदद से चूहे और मृगियों की टूटी हड्डियों को जोड़ने में सफलता हाथ लगी है। अब हम साल के अंत तक इनसानों हड्डियों पर इसका असर आंकने की तैयारी कर रहे हैं। हम के अनुसार हड्डियों को जोड़ने के लिए जब प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो शरीर में सबसे पहले एक कार्टिलेज बनता है। यह एक ढांचे की तरह काम करता है, जिसके इर्दगिर्द हड्डी विकसित होती है। व्यक्ति जितना व्यायाम करता हड्डी जल्दी ही मजबूत बनेगी। हालांकि अमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता। हड्डी टूटने पर मरीज को असह्यनीय दर्द होता है। हमने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए स्टेम सेल से भरपूर जैल बनाया है। इसका इंजेक्शन लगाने पर मरीज को बिस्तर से उठने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी और उसकी टूटी हड्डी न सिर्फ जुड़ेगी, बल्कि उसका घनत्व भी अधिक होगा।

जूतों की शॉपिंग ऐसी हो कि आपको देखकर सब हो जाएं हैरान

महिलाओं की पसंदीदा एक्सेसरीज में से एक हैं उनके फुटवियर्स। इसे चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, सही फुटवियर के बिना अधूरी रह जाती है। अब इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप डेढ़ जूते खरीद कर घर ले आए। हम आपको जूतों की शॉपिंग के लिए ऐसे टिप्स देंगे कि आपकी वार्डरोब देखकर आपकी सहेलियां भी आपसे ईर्ष्या करने लगे। ये वो टैपर्स हैं जो आपकी हर आउटफिट की अपीयरेंस और भी ग्लैमरस बना देंगे।

फुटवियर्स से आउटफिट बनाएं ग्लैमरस

ईवनिंग पार्टी के लिए व्लासी ब्लैक

ईवनिंग पार्टी और आम मौकों पर पहनने के लिए हर लड़की के पास क्लासी ब्लैक पम्पस का एक पेयर जरूर होना चाहिए। इसे आप किसी भी अवसर पर पहन सकती हैं। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रही हैं, तो भी ये फुटवियर खूबका चबड़ा रहेगी। ये शूज पर्फेक्ट हैं, लेकिन ईवनिंग वियर के साथ बेहतरीन लुक देंगे। हल्की होल घाले ये शूज काफी आगमचक होते हैं और पैरों को आराम भी देते हैं। इन्हें पहन कर चलना आसान रहता है। आजकल ट्रेंडी फुटवियर में कोलरापुरी चप्पलें और मोजरी का फैशन इन है।



बैली निखारेगी पर्सनैलिटी, पैरों के लिए आरामदायक

अगर आप फुटवियर्स के मामले में ज्यादा हमले में नहीं पड़ना चाहती और बहुत सिंपल शूज चाहती हैं लेकिन साथ ही एलिगेंट लुक भी चाहती हैं तो बैली आपकी सभी अजमाइशों पर खरी उतरती है। ये आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारेगी। अगर इन्हे सारा दिन पहन सकती हैं, इसके बावजूद आपके पैरों में दर्द नहीं होगा क्योंकि ये बेहद आरामदेय होती हैं। आप इन्हें फॉर्मल आउटफिट के साथ पहन सकती हैं और अगर चाहें तो डॉक के साथ भी कैरी कर सकती हैं।

स्टेपी सैंडल्स से मिलेगा बोल्ल लुक

अगर आप सोशल हैं तो बहुत सारे विशेष अवसरों पर आपको जाना पड़ता है, ऐसे में आप अपना फैशन दिखा सकती हैं। फॉर्ब्स में थोड़ी-सी एक्साइटिंग क्लिंग की जरूरत होती है। ग्लैम लुक के लिए गोल्ड या सिल्वर में स्टेपी सैंडल्स ट्राई करें। इस पर बड़े बोल्ल स्टोस लगे हो सकते हैं। मोती भी इनकी चमक को और बढ़ाएंगे और आपको रोशनी व बोल्ल लुक देंगे। अगर आपको एथनिक वियर्स ज्यादा पसंद हैं या जोस और स्कर्ट पहनना आपको ज्यादा भाता है तो वेसिक कलर्स जैसे बेज, ब्लैक या कैमल ट्राई करने चाहिए। ये भारतीय परिधानों और लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ सुंदर दिखते हैं। न्यूट्रल कलर्स से आप ऑफिकनर आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकती हैं।

...तो अब ब्लड शुगर को कर सकेंगे नियंत्रित

हम में से अधिकांश खाना पकाने में रिफाईंड अनाज का प्रयोग करते हैं। वह ऐसा अनाज है जिसकी बाहरी परत नहीं होती। इस बाहरी परत को व्हीट ब्रान कहते हैं। इसमें विटामिन बी-1, बी-2, बी-3, विटामिन-ई, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कोपर तथा फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके बिना हमारा अनाज उतना स्वस्थ नहीं होगा जितना कि वह हो सकता है। चलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं तो आपको साबुत अनाज के बारे में सोचना होगा। आइए जानते हैं इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में।



लिवर को बनाता है स्वस्थ

एक स्वस्थ लिवर के लिए एक ऐसे फूट की जरूरत होती है, जिसमें भोजन आसानी से ड्रयर-ड्रयर आ-जा सके और जो थोड़े लहकों के निमित्त होने से रहित हो। साबुत अनाज का ब्रान वाला हिस्सा इस बात को यकीनी बनाता है कि इन विषैले तत्वों को प्रभावी ढंग से साफ किया जाए।

अधिक पोषक...
लुकि व्हीट ब्रान साबुत अनाज में से रटया नहीं जाता और सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं इसलिए खिलाड़ियों, बढ़ रहे बच्चों, मां बनने वाली महिलाओं तथा स्वस्थ भोजन की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसकी सलाह दी जाती है। साबुत अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्कोर आटे के मुकाबले ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करता है। व्हीट ब्रान भोजन को ब्लड शुगर में धीरे-धीरे परिवर्तित करता है और इसे शरीर के प्राकृतिक इंसुलिन हार्मोन मैकेनिज्म के लिए आसानी से मैनेज करता है।

कैंसर का खतरा कम
साबुत अनाज का आटा फाइबर का बहुत बढ़िया स्रोत है जो हमारी आंतों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। भोजन में फाइबर वाला हिस्सा अधिक होता चाहिए ताकि यह पानी अधिक सोख सके। आंतों के प्रो-बायोटिक बैक्टीरिया को पेट स्क्रेप आटे के मुकाबले ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करता है। व्हीट ब्रान भोजन को ब्लड शुगर में धीरे-धीरे परिवर्तित करता है और इसे शरीर के प्राकृतिक इंसुलिन हार्मोन मैकेनिज्म के लिए आसानी से मैनेज करता है।

रौस्टड वेंजिटेबल्स के लिए: एक चौड़े नॉन-स्टिक पैन में जैतून का तेल गरम करें, लहसुन का पेंस्ट डालकर मध्यम आँव पर 30 सेकंड तक भूनें। ताल और हरी शिमला मिर्च के टुकड़े और 2 टैबल-स्पून पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें और बीच-बीच में हिलाते हुए, धीमी आँव पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। टमाटर, औरिगानो, लाल मिर्च के फ्लैक्स और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें और बीच-बीच में हिलाते हुए, मध्यम आँव पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। एक तरफ रखें। **आगे बढ़ने की विधि:** रौस्टड वेंजिटेबल्स और व्हाइट सॉस को एक चौड़े नॉन-स्टिक पैन में डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आँव पर, बीच-बीच में हिलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लें। एक तरफ रख दें। बेकिंग डिश के बेंस पर 1/2 कप पिज्जा सॉस डालकर अच्छी तरह फैला लें और सॉस के ऊपर समान अंतर पर 2 लज्जानीया शीट रखें। व्हाइट सॉस-रौस्टड वेंजिटेबल्स के मिश्रण को डालकर फैला लें और इसके ऊपर 1/4 कप पिज्जा सॉस फैलाकर ऊपर और 2 लज्जानीया शीट्स रखें। बचा हुआ 1/4 कप पिज्जा सॉस डालकर अच्छी तरह फैला लें और ऊपर अच्छी तरह से चीज छिड़के। पहले से गरम अवन में लज्जानीया को 200°C (400°F) के तापमान पर 8 मिनट के लिए बेक करें या माइक्रोवेव में उब पर 2 मिनट के लिए पका लें। गार्लिक ब्रेड के साथ तुरंत परोसे।

विधि
रौस्टड वेंजिटेबल्स के लिए: एक चौड़े नॉन-स्टिक पैन में जैतून का तेल गरम करें, लहसुन का पेंस्ट डालकर मध्यम आँव पर 30 सेकंड तक भूनें। ताल और हरी शिमला मिर्च के टुकड़े और 2 टैबल-स्पून पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें और बीच-बीच में हिलाते हुए, धीमी आँव पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। टमाटर, औरिगानो, लाल मिर्च के फ्लैक्स और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें और बीच-बीच में हिलाते हुए, मध्यम आँव पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। एक तरफ रख दें। बेकिंग डिश के बेंस पर 1/2 कप पिज्जा सॉस डालकर अच्छी तरह फैला लें और सॉस के ऊपर समान अंतर पर 2 लज्जानीया शीट रखें। व्हाइट सॉस-रौस्टड वेंजिटेबल्स के मिश्रण को डालकर फैला लें और इसके ऊपर 1/4 कप पिज्जा सॉस फैलाकर ऊपर और 2 लज्जानीया शीट्स रखें। बचा हुआ 1/4 कप पिज्जा सॉस डालकर अच्छी तरह फैला लें और ऊपर अच्छी तरह से चीज छिड़के। पहले से गरम अवन में लज्जानीया को 200°C (400°F) के तापमान पर 8 मिनट के लिए बेक करें या माइक्रोवेव में उब पर 2 मिनट के लिए पका लें। गार्लिक ब्रेड के साथ तुरंत परोसे।

कलिंग समाचार



संपादकीय

दलित क्या पानी पीने के हकदार नहीं

देश में धार्मिक और जातीय भेदभाव के कारण समाज में जो दुश्मनी का माहौल बन गया हैए अब उसमें इसी तरह इंतिकाम यानी बदला लेने की घटनाएं हो रही हैं। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के वेंगईवयाल गांव में एक झकझोरने वाला मामला सामने आया है। इस गांव के बच्चे पिछले कुछ दिनों से बीमार पड़ रहे थे। डाक्टर ने बीमारी का पता लगाने के लिए पानी की जांच करने कहा। गांव में जिस पानी की टंकी से आपूर्ति होती थीए उस पर चढ़कर देखा गया तो पानी पीला नजर आया। जांच के बाद पता चला कि लगभग 10 हजार लीटर वाली इस पानी टंकी में किसी ने बड़ी मात्रा में मानव मल डाल दियाए ताकि पानी दूषित हो जाए। यह अमानवीय कृत्य केवल इसलिए हुआए क्योंकि वेंगईवयाल गांव आज भी दलित विरोधी मानसिकता से जकड़ा हुआ है। एक और चिंताजनक और हैरान करने वाली बात ये है कि यह खबर देते हुए कुछ लोगों ने अनुसूचित या दलित समुदाय के लिए बनी पानी टंकी लिखा है। हमने प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं तो पढ़ी हैए लेकिन आजादी के अमृतकाल में भी अगर दलितों की पानी टंकी पढ़ना पड़ेए तो ये समझना कठिन नहीं है कि आजादी का अमृत केवल सवर्ण.संपन्न तबकों के लिए ही है। गरीब पहले भी गुलाम थेए अब भी उनके हालात गुलामों की तरह ही बदतर हैं। जिस गांव में दलितों के पानी पीने पर भी साजिश रची गईए वहां इस बात का भी खुलासा हुआ है कि यहां जातिगत भेदभाव हर जगह है। गांव में चाय की दुकान पर दलितों के लिए अलग गिलास रखे हुए हैं। दलितों का ये भी कहना है कि उन्हें तीन पीढ़ियों से मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है। पानी टंकी को मानव मल से दूषित करने की शिकायत के बाद जब यहां की जिलाधिकारी कविता रामू और पुलिस अधीक्षक वंदिता पांडे गांव में पहुंचीं तब लोगों ने इन सारे भेदभाव की शिकायत की। बताया जा रहा है कि जिस चाय दुकान में दलितों के लिए अलग गिलास रखने का रिवाज थाए उसके मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने की पहल भी जिलाधिकारी ने की। उन्होंने कहा कि मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खुले होने चाहिए और सभी को यहां दर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए यहां कैमरे लगाए जाएं। जिलाधिकारी दलित समुदाय के लोगों को मंदिर के अंदर ले गईं। लेकिन खबरों के मुताबिक जिस समय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचीं तो वहां पर पूजा चल रही थीए उसी दौरान कथित रूप से ऊंची जाति की एक महिला ने अपने शरीर में देवता के आने की बात कही और कहा कि नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर यह बात सही है तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि जिलाधिकारी की इस स्वागतयोग्य पहल का कोई भविष्य नहीं है। दरअसल जाति की बेड़ियों ने समाज को इस तरह बांधा हुआ है कि उसे टूटने में सदियां लग जाएंगी। वैसे यह विचारणीय है कि वेंगईवयाल गांव में अगर पानी टंकी का दुखद प्रकरण घटित नहीं होताए तो क्या पुडुकोट्टई जिला प्रशासन को दलितों के साथ हो रहे भेदभाव की खबर लग पाती। अगर तीन पीढ़ियों से दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं मिला थाए तो यह बात पहले से प्रशासन के संज्ञान में क्यों नहीं थी। जो भेदभाव जिले के एक गांव में हुआ हैए क्या अन्य गांवों.शहरों का भी वही हाल नहीं होगा। दुखद बात ये है कि दलितों के साथ ये अन्याय उस तमिलनाडु में हुआए जो ई वी रामास्वामी पेरियार की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रहीं। पेरियार ने पूरी जिंदगी अंधविश्वासए अतार्किकताए रूढ़िवादी विचारों और ब्राह्मणवाद की मुखालफ्त की। उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफबताया जाता हैए लेकिन असल में वे सभी संगठित धर्मों के खिलाफथे। पेरियार हर तरह के भेदभाव के खिलाफथेए चाहे वह जाति या धर्म को लेकर हो या फिर लैंगिक आधार पर। इसलिए उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलनए विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकारए पार्टनर चुनने या छोड़नेए शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेनेए आदि के लिए अभियान चलाया था।

भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना के विस्तार की आवश्यकता

नन्तु बनर्जी
भारतीय नौसेना की वर्तमान बेड़े की ताकत उत्तर कोरियाए कोलंबियाए मिस्रए थाईलैंड और ईरान की तुलना में भी कम है। 2020 तकए भारतीय नौसेना की वास्तविक बेड़े की ताकत की तुलना में पीएलएएन के बेड़े का आकार ;विमान वाहक और पनडुब्बियों सहित 777 युद्धपोतद्ध काफी बड़ा था। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलएएन के कुल बेड़े का आकार ३४5 गश्ती लड़ाकों और शिल्प को शामिल नहीं करता है जो एंटी.शिप क़रूज मिसाइल ;एएससीएमद्ध ले जाते हैं।ए भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए भारत को आने वाले वर्षों में तेजी से पूंजीगत बजट को बढ़ाना होगाए अपने बेड़े को विस्तारित करना होगाए और आधुनिकीकरण की गति तेज करनी होगी ताकि आकार में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना शक्तिए चीन की पीोपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ;पीएलएएनद्ध से हिंद महासागर तथा प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते खतरों का मुकाबला किया जा सके। सरकार को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि पीएलएएन भारतीय नौसेना से चार गुना बड़ा और मजबूत है। यह सच है कि इस वित्तीय वर्ष में पहली बार भारतीय नौसेना का पूंजीगत व्यय लक्ष्य 45 प्रतिशत तक बढ़ाया गया हैए परन्तु आगे भी इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

पिछले साल के 21000 करोड़ की तुलना में 2022.23 के लिए अकेले जहाजों और उपकरणों के लिए बजट आबंटन 35ए452 करोड़ रुपये था। कुल पूंजी परिव्यय का 75 प्रतिशत इसके बेड़े के लिए निर्धारित किया गया हैए जिसमें युद्धपोतए पनडुब्बी और अन्य उपकरण शामिल हैं। देश के नौसैनिक बल को 2023.24 और उसके बाद भी इसी तरह के बजट की ज़रूरत है। भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में बढ़ते पीएलएएन के खतरे का सामना करने के लिए अपनी क्षमता को मजबूती से बढ़ाने की आवश्यकता हैए विशेष रूप से भारत के तीन महासागर साझा करने वाले पड़ोसियों– बांग्लादेशए श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते सैन्य गठबंधन के संदर्भ में।

दुर्भाग्य सेए भारतीय नौसेना को वह प्राथमिकता नहीं मिलीए जिसकी वह पहले के वर्षों में सरकार से हकदार थी। भारतीय नौसेना की वर्तमान बेड़े की ताकत उत्तर कोरियाए कोलंबियाए मिस्रए थाईलैंड और ईरान की तुलना में भी कम है। 2020 तकए भारतीय नौसेना की वास्तविक बेड़े की ताकत की तुलना में पीएलएएन के बेड़े का आकार ;विमान वाहक और पनडुब्बियों सहित 777 युद्धपोतद्ध काफी बड़ा था। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलएएन के कुल बेड़े का आकार 85 गश्ती लड़ाकों और शिल्प को शामिल नहीं करता है जो एंटी.शिप क़रूज मिसाइल ;एएससीएमद्ध ले जाते हैं।ए 2020 तकए भारतीय नौसेना की वास्तविक बेड़े की ताकत की तुलना में पीएलएएन के बेड़े का आकार ;विमान वाहक और पनडुब्बियों सहित 777 युद्धपोतद्ध काफी बड़ा था। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलएएन के कुल बेड़े का आकार 85 गश्ती लड़ाकों और शिल्प को शामिल नहीं करता है जो एंटी.शिप क़रूज मिसाइल ;एएससीएमद्ध ले जाते हैं।ए वर्षा भूभाणी मिर्ज़ा
इस हिंसा को उकसाते हुए सभी लड़कियों के साथ लड़कों की भी सुरक्षा भूल रहे हैं या इन अपराधों से आंखें मूंदे हुए हैं। बलात्कार के चालीस फ़ीसदी केस वास्तव में बलात्कार के नहीं होते। ये वे मामले हैं जिनमें परिवार उन पुरुषों को बलात्कार के इल्ज़ाम में मुकदमे दायर करता है जिनसे परिवार की बेटियां या तो शादी कर चुकी होती हैं या करना चाहती हैं। परिवार हर कोमत पर इन शादियों को निरस्त कर लड़की को बरामद करना चाहते हैं। क्या यह महज संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी दो स्त्रियां जिनमें एक सांसद और दूसरी मंत्री हैंए एक ही समय में कहती हैं कि श्वात्मरक्षा के लिए हथियार रखो और अपने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू की धार इतनी तेज करा लो ताकि वक्त आने पर दुश्मन के सर काट सकोष्छ किसके लिए करने हैं ये हथियार धारदारष् क्या किसी भी बंदूक की गोली या हथियार पर लिखा होता है कि वह किसकी जान लेगीष् क्या यह तय है कि ये हथियार चुन.चुनकर निशाना साधेंगे और समाज में हिंसा के बाद फिर संस्कार पर लौट आएगाष् क्या ऐसे संस्कारित होंगी देश की लड़कियां जिनकी बात सांसद महोदया करती हैंष् आखिर क्यों जिं मेदार पदों पर बैठे इन लोगों को संसदए सरकार और देश की व्यवस्था से कोई उ मीद नहीं है जो ये भीड़ को उकसा.उकसाकर हिंसक हो जाने के लिए कह रहे हैं६ देश के कानून में ऐसी नफ़्ती और घृणा फैलाने वाली भाषा के लिए कोई जगह नहीं

आने वाले वित्तीय वर्षों में भारतीय नौसेना के लिए एक ब पर बजट आबंटन मौजूदा जहाजों और पनडुब्बियों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा और इसके बेड़े के आकार को भी बढ़ायेगा क्योंकि चीन अपनी नौसैनिक पहुंच को और बढ़ा देगा। अमेरिकाए जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी अत्याधुनिक नौसैनिक शक्तियों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी–चतुर्भुज सुरक्षा संवाद ;क्राइड के सभी सदस्य.बहुत कम मूल्य की होगी यदि भारतीय नौसेना स्वयं पर्याप्त मजबूत नहीं है। हालांकि अमेरिकी बेड़े का आकार ;490 जहाजद्ध चीन की तुलना में छोटा हैए यह घातक शक्ति में पीएलएएन की तुलना में काफी मजबूत है। वास्तव मेंए अमेरिकी नौसेनाए मारक क्षमता के मामले मेंए विमान वाहक और पनडुब्बियों की बेजोड़ ताकत के साथ सबसे आधुनिक और बहुमुखी मानी जाती है।

वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ़ मॉडर्न वारशिप्स 2023 अमेरिकी नौसेना को दुनिया की सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति मानती हैए इसके बाद पीएलएएन, रूसी नौसेना, इंडोनेशियाई नौसेना, कोरिया गणराज्य की नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना का स्थान है। अमेरिकी नौसेना के पास 11 विमान वाहकए 10 हेलीकॉप्टर वाहकए 68 पनडुब्बी और 92 विध्वंसक हैं। केवल पीएलएएन के पास अधिक पनडुब्बियां ;79द्ध हैं।

पर आतंकी हमले के वक्त नीचे आर्डर पास कर सकते थे लेकिन उन्होंने मोर्चा खुद संभाला। अपेक्षाकृत कमज़ोर बुलेटप्रूफ़ हेलमेट जो उनका नहीं था और रायफल के साथ मैदान में कूद पड़े। सीने पर गोलियां खाईं। ये तथ्य उस समय की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में हैं। वही हेमंत करकरे मालेगांव बम विस्फ़ोट कांड की भी जांच कर रहे थे जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक आरोपी थीं। सवाल यही है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुखर विरोध करने वाली पार्टी यहां जान की बाज़ी लगा देने वालों के लिए पूर्वाग्रही कैसे हो जाती हैय और फिर यह कैसा दर्द है जो उन्हीं प्रज्ञा को 2019 में भोपाल से लोकसभा का टिकट दिलवा देता है। आप उन्हें संसद बना देता है। आप कहेंगे कि सांसद तो जनता ने बनाया। उसने जितायाए बेशक जनता जो वोट देती हैए जिं मेदार है। यहां इस क्रोनोलांजी पर भी निगाह डालने की ज़रूरत है कि गुजरात में जो बिल्किस बानो दंगों के दौरान बलात्कार और परिजनों की हत्या का शिकार होती हैं उसके सजाया ता अपराधी रिहा कर दिए जाते हैं और जो सांसद कहती हैं कि श्अपनी बेटियों को सुरक्षित रखोए अपनी बेटियों को संस्कारित करोए अपने घर में हथियार रखोए कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू ज़रा तेज रखो! स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए जो चाकू है उसे तेज रखो। जो सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के सर भी अच्छे से कटेंगे। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं

रूस में 64 पनडुब्बियां हैं। चीन के 50 और रूस के 15 के मुकाबले अमेरिका के पास 92 विध्वंसक हैं। हालांकि ये अनुमान हमेशा अन्य वैश्विक श्नेवल वॉचश् रिपोर्ट से मेल नहीं खाते। इसके अलावाए श्सबसे बड़े श् नौसैनिक बलों का मतलब श्सबसे शक्तिशालीश् बलों से नहीं है। विभिन्न श्नौसेना निगरानीश् एजेंसियां इस बारे में विपरीत दिशानिर्देश देती हैं कि वे किस प्रकार के जहाज को किसी देश की नौसेना का हिस्सा मानते हैं। उदाहरण के लिएए चीन की नौसेना में इससे100 से अधिक होवरक्रा ट शामिल हैंए जिन्हें नौसैनिक जहाज माना भी जा सकता है और नहीं भी। आधुनिक नौसैनिक बल अक्सर न केवल सक्रिय ड्यूटी पर कमीशन किये गये जहाजों को शामिल करते हैंए बल्कि गैर.कमीशन वाले जहाजोंए सहायक जहाजोंए आरक्षित बेड़े और यहां तक कि निर्माणाधीन जहाजों को भी शामिल करते हैं। ऐसी गणनाओं में हो सकता है किसी देश की नौसेना के जहाजों की सं या पर प्रभाव का अनुमान है।

आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसारए भारतीय नौसेना के पास 150 युद्धपोत और पनडुब्बियांए चार इंधन टैंकरए एक जवाबी पोतए 24 जलपोतए पनडुब्बीरोधी युद्धक उथले जल जहाज, 17 हमलावर पनडुब्बियांए एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बीए 14 फ़्रिगेट, 10 विध्वंसक, तथा 300 विमान हैं। आठ लैंडिंग शिप टैंकए एक उभयचर परिवहन डॉकए दो विमान वाहकए विभिन्न छोटी पेट्रोल नौकाएंए पूरक जहाज भी हैं। भारतीय नौसेना के पास लगभग 75000 रिजर्व और 67000 से अधिक सक्रिय कर्मी हैं। इसके पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूहए पश्चिम बंगालए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्रए गोवाए कर्नाटक और गुजरात में पूरी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षण आधार हैं। इन आधारों से गोला.बारूद समर्थनए रसद और रखरखाव सहायताए समुद्री कमांडो आधारए वायु स्टेशनए आगे संचालन आधारए पनडुब्बी और मिसाइल नाव आधारए मिसाइल रक्षा और तटीय रक्षा प्रदान करने वाले हैं। भारत की नौसेना जल्द ही एक मजबूत वैश्वक नौसैनिक शक्ति बनने की आकांक्षा रखती है। नेशनल इन्टरेस्ट डॉट ऑर्ग पर सैन्य विश्लेषकों की 2021 की एक रिपोर्ट में 2030 में दुनिया की पांच शीर्ष नौसेनाओं का अनुमान लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसने भारतीय नौसेना को रूस से आगे चौथे स्थान पर रखा। यह रिपोर्ट अगले आठ वर्षों में भारतीय नौसेना के विस्तार के बारे में अति.आशावादी है। अमेरिकी नौसेना नंबर 1 हैए उसके बाद ब्रिटिश नौसेना और चीनी नौसेना है। विश्लेषकों को उ मीद है कि टन भार और तकनीकी प्रगति के बेजोड़

अभिभावक भी यहां पहुंचकर उनके पंख कतरना चाहते हैं। झुमरीतलैयाए बिहार की निरुपमा के साथ भी यही हुआ। पुलिस ने परिजनों को गिर तार करते हुए आरोप लगाया कि उसने खुदकुशी नहीं कीए उसकी गला दबाकर हत्या की गयी थी। वह दस ह ते के गर्भ से थी। दरअसलए हर मध्यमवर्गीय भारतीय परिवार बच्चों की शादी के ज़रिये यह साबित करते हैं कि हमारे बच्चों पर हमारी कितनी नकेल है। अपने बच्चों को जी.जान से पालने वाले आखिर इतने कटु और स त क्यों हो जाते हैंष् इसलिए क्योंकि नेता और इनकी व्यवस्था इन बच्चों की रक्षा करने का आश्वासन नहीं देतीष् सब जानते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम कमज़ोर किया जा रहा है। इस हिंसा को उकसाते हुए सभी लड़कियों के साथ लड़कों की भी सुरक्षा भूल रहे हैं या इन अपराधों से आंखें मूंदे हुए हैं। बलात्कार के चालीस फ़ीसदी केस वास्तव में बलात्कार के नहीं होते। ये वे मामले हैं जिनमें परिवार उन पुरुषों को बलात्कार के इल्ज़ाम में मुकदमे दायर करता है जिनसे परिवार की बेटियां या तो शादी कर चुकी होती हैं या करना चाहती हैं। परिवार हर निरस्त कर लड़कों को बरामद करना चाहते हैं और लड़कों को सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं। ये लड़कियां कभी घरों में कैद कर दी जाती हैं तो कभी नारी निकेतनों में। यह सोच ही बहुत बचकानी है कि लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। वह परिवार जिसका बेटा महज़ प्रेम करने के जुर्म में बलात्कार या अपहरण

संयोजन के कारण अमेरिका प्रमुख वैश्वक नौसैनिक शक्ति बना रहेगा।

अमेरिकी नौसेना के पास न केवल बहुत से जहाज़ हैंए बल्कि इसके पास कई विशालए अत्याधुनिक जहाज़ भी हैं। यूके के जहाजों की कुल सं या में कमी आने की उ मीद है। दो नये विमान वाहकों को जोड़ने और इसके पनडुब्बी बेड़े में वृद्धि से ब्रिटेन को नंबर 2 समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित होना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है और उसके पास 2030 तक तीन ऑपरेटिंग विमान वाहक होने चाहिएए जो सामूहिक रूप से 110.120 विमानों को तैनात करने में सक्षम हों। आधिकारिक रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय नौसेना के पास विभिन्न प्रकार के 45 पोत निर्माणाधीन हैं।

इनमें विध्वंसक, फ़्रिगेट, जलपोत, पारंपरिक और परमाणु.संचालित पनडुब्बियां शामिल हैं। योजना 2050 तक 200 युद्धपोतों और 500 विमानों की एक मजबूत नौसेना बनाने की है। चीन की आक्रामक मुद्रा और भारत.प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए समय सीमा काफी लंबी प्रतीत होती है। सरकार को वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने विस्तार कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भारतीय नौसेना को वार्षिक पूंजीगत व्यय निधि सहायता जारी रखनी चाहिए।

तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई

वर्षा भूभाणी मिर्ज़ा

इस हिंसा को उकसाते हुए सभी लड़कियों के साथ लड़कों की भी सुरक्षा भूल रहे हैं या इन अपराधों से आंखें मूंदे हुए हैं। बलात्कार के चालीस फ़ीसदी केस वास्तव में बलात्कार के नहीं होते। ये वे मामले हैं जिनमें परिवार उन पुरुषों को बलात्कार के इल्ज़ाम में मुकदमे दायर करता है जिनसे परिवार की बेटियां या तो शादी कर चुकी होती हैं या करना चाहती हैं। परिवार हर कोमत पर इन शादियों को निरस्त कर लड़की को बरामद करना चाहते हैं। क्या यह महज संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी दो स्त्रियां जिनमें एक सांसद और दूसरी मंत्री हैंए एक ही समय में कहती हैं कि श्वात्मरक्षा के लिए हथियार रखो और अपने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू की धार इतनी तेज करा लो ताकि वक्त आने पर दुश्मन के सर काट सकोष्छ किसके लिए करने हैं ये हथियार धारदारष् क्या किसी भी बंदूक की गोली या हथियार पर लिखा होता है कि वह किसकी जान लेगीष् क्या यह तय है कि ये हथियार चुन.चुनकर निशाना साधेंगे और समाज में हिंसा के बाद फिर संस्कार पर लौट आएगाष् क्या ऐसे संस्कारित होंगी देश की लड़कियां जिनकी बात सांसद महोदया करती हैंष् आखिर क्यों जिं मेदार पदों पर बैठे इन लोगों को संसदए सरकार और देश की व्यवस्था से कोई उ मीद नहीं है जो ये भीड़ को उकसा.उकसाकर हिंसक हो जाने के लिए कह रहे हैं६

देश के कानून में ऐसी नफ़्ती और घृणा फैलाने वाली भाषा के लिए कोई जगह नहीं हैए लेकिन अकेले जहाजों और उपकरणों के लिए बजट आबंटन 35ए452 करोड़ रुपये था। कुल पूंजी परिव्यय का 75 प्रतिशत इसके बेड़े के लिए निर्धारित किया गया हैए जिसमें युद्धपोतए पनडुब्बी और अन्य उपकरण शामिल हैं। देश के नौसैनिक बल को 2023.24 और उसके बाद भी इसी तरह के बजट की ज़रूरत है। भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में बढ़ते पीएलएएन के खतरे का सामना करने के लिए अपनी क्षमता को मजबूती से बढ़ाने की आवश्यकता हैए विशेष रूप से भारत के तीन महासागर साझा करने वाले पड़ोसियों– बांग्लादेशए श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते सैन्य गठबंधन के संदर्भ में।



पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन ने गांवों का किया दौरा, लोगों की समस्याएं सुनी

जालंधार। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने गोराया और फिल्लौर ब्लॉकों के गांवों का दौरा करके लोगों की समस्याएं सुनी, इसी श्रृंखला के तहत आज उन्होंने गांव रुड़का कलां, रुड़की, अकलपुर, गांव गन्ना और गोराया के मोहल्ला लांगडियां का दौरा कर लोगों की समस्याओं की सुनवाई की। अपने दौरे के दौरान श्री गढ़ी ने विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याएं सुनते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रशासन के साथ समन्वय करके उनके मुद्दों का उचित समाधान सुनिश्चित किया

जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रत्येक वर्ग के लोगों की भलाई और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान चेयरमैन ने यूथ फुटबॉल क्लब, रुड़का कलां पहुंचकर मैक्सिको में हुए स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के कारण रनरअप का गौरव हासिल करने वाली टीम का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने क्लब को एक लाख एक हजार रुपये देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि वाई.एफ.सी. द्वारा युवाओं को खेलों से जोड़कर स्वस्थ समाज की रचना में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तर्ज पर और भी पहल होनी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को खेलों से जोड़कर नशों से दूर रखा जा सके। श्री गढ़ी ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि राज्य में खेल संस्कृति को और अधिक प्रफुल्लित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 'खेड़ा वतन पंजाब दिया' के अलावा आधुनिक सुविधाओं से लैस 3000 से अधिक खेल मैदानों को विकसित करने, खिलाड़ियों के उचित सम्मान सहित कई

पहल की हैं। उन्होंने क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए वाई.एफ.सी. के चेयरमैन गुरमंगल दास, क्लब की प्रबंधक कमेट्री और खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके अलावा डेरा बाबा भाई साधू जी, सरपंच इकविंदर कौर और गांव वासियों का युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। दौरे के दौरान श्री गढ़ी ने मंदिर बाबा श्री बालक नाथ जी गोराया, डेरा बाबा भाई साधू जी रुड़का कलां और डेरा बाबा ब्रह्मदास अकलपुर में नतमस्तक होकर सूबा वासियों की तरक्की और

खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उपरांत भगवान वाल्मीकि आश्रम प्रबंधक कमेट्री गोराया के साथ बैठक के दौरान आश्रम के निकट कूड़े के ढंप को हटाने की मांग पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा देते हुए श्री गढ़ी ने कहा कि इस संबंध में नगर परिषद, गोराया को निर्देश जारी करके उचित कार्रवाई के लिए बाध्य किया जाएगा। अंत में श्री गढ़ी ने गांव गन्ना पहुंचकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं का उचित समाधान करवाया जाएगा और भाईचारे के लोगों के मुद्दे जल्द से जल्द हल करवाए जाएंगे।

नाटक 'बियॉंड द इमेजिनेशन' का तीन दिवसीय मंचन

रोहतक। दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) में नाटक 'बियॉंड द इमेजिनेशन' का तीन दिवसीय मंचन जाएगा। फिल्म एवं टेलीविजन फैंकेल्टी के मिनी ऑडिटोरियम में होने वाले मंचन में थियेटर, नाटक व कला प्रेमियों के लिए एंट्री निशुल्क रहेगी। नाटक का मंचन एक्टिंग डिपार्टमेंट के छात्र करेंगे। वे तीन दिवसीय मंचन के दौरान इसके पांच बार शो प्रस्तुत करेंगे। एफटीवी के फैंकेल्टी कॉर्डिनेटर महेश टीपी ने बताया कि 'बियॉंड द इमेजिनेशन' प्रसिद्ध मराठी नाटक प्रतिबिंब पर आधारित है, जिसे जाने-माने लेखक, साहित्यकार महेश एलकुंचवार ने लिखा है। एक्टिंग के चौथे सेमेस्टर के छात्र भारती, प्रिंस व पुष्कर इसके मुख्य पात्र होंगे, जो लगातार तैयारी में जुटे हैं। इसके निर्देशक एनएसडी से स्नातक सुशील कांत रहेंगे, जबकि प्रॉडक्शन डिजाइन की जिम्मेदारी बिपिन गोबाले की रहेगी। एनएसडी की ही पूर्व छात्रा पाली फुकोंन कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रही हैं। इसका हिंदी अनुवाद वसंत देव ने किया है, जबकि साउंड की जिम्मेदारी दीपा वर्मा संभालेंगी। दर्शकों को थियेटर वाला अनुभव महसूस कराने के लिए मिनी ऑडिटोरियम के मंच पर नाटक का सेट तैयार किया जा रहा है। बाहर से आई एक्सपर्ट की टीम सुपवा के छात्र कलाकारों की लगातार रिहर्सल कराने में जुटी है।

आईआईटी में फेल होने से गुगल तक का सफर, हरियाणा के लड़के ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मां के लिए लगवाया बिलबोर्ड

पंचकूला। हरियाणा के एक छोटे से शहर पंचकूला के रहने वाले अभिजय अरोड़ा ने कामयाबी की एक ऐसी नई इबारत लिखी है, जिसने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक, गूगल में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद अभिजय ने अपनी 'सिंगल मदर' को सम्मान देने के लिए एक ऐसा अनोखा तरीका चुना, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अभिजय ने न्यूयॉर्क के बेहद मशहूर और महंगे 'टाइम्स स्क्वायर' के एक बड़े बिलबोर्ड पर अपनी मां की तस्वीर लगवाकर उन्हें एक लाइफ-वेंजिंग सरप्राइज दिया। जब वीडियो कॉल के दौरान मां ने सात समंदर पार अमेरिका के सबसे आलीशान चौराहे पर खुद को देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इस बेहद भावुक पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभिजय की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे उनकी मां के संघर्षों की एक लंबी और दर्दभरी दास्तान है।

की असफलता ने अभिजय को टूटने नहीं दिया, बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया। हालांकि, रास्ते इतने आसान नहीं थे। साल 2016 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी उन्हें नौकरी के लिए दर-दर भटकना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। साल 2017 में एक प्रतिष्ठित हैकाथॉन जीतने के बाद उनका हौसला बढ़ा।

इसके बाद 2016 से 2020 तक उन्होंने किसी बड़ी कंपनी के पीछे भागने के बजाय चुपचाप जीमैट की कठिन तैयारी शुरू की। तीन बार परीक्षा देने और साल 2021 में कई टॉप बिजनेस स्कूलों से रिजेक्शन मिलने के बाद आखिरकार साल 2022 में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद साल 2025 में उनकी मेहनत रंग लाई और गूगल ने उन्हें एक बड़े पद पर चुन लिया। अभिजय ने इस भावुक पल की तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए एक बेहद दिल छू लेने वाला नोट लिखा। उन्होंने लिखा, "यह मेरे जीवन का सबसे खास दिन था। मैं अपनी मां को टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर दिखाकर दुनिया के सामने उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। इस एक बेहद साधारण परिवार से हैं, लेकिन मेरी मां ने पाला और उन्हें बेहतरीन शिक्षा दिलाई। अभिजय के मुताबिक, उनकी मां ने खुद हमेशा 'सेकेण्ड हैंड' (पुरानी) किताबों से पढ़ाई की और अपने सारे सपनों की कुर्बानी देकर बेटे का भविष्य संवारा। साल 2012 में जब अभिजय आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, तो उनकी मां बुरी तरह टूटकर रो पड़ी थीं। उसी दिन रोते हुए अभिजय ने अपनी मां से वादा किया था कि एक दिन वह उन्हें दुनिया का सबसे गौरवान्वित माता-पिता बनाएंगे। आईआईटी

दोआबा में, वसंत ऋतु में उगने वाली मूंगफली की फसल मक्का के विकल्प के रूप में उभरी : सीचेवाल

फगवाड़ा। पंजाब के दोआबा क्षेत्र में वसंत ऋतु में मूंगफली की खेती ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। भूजल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मूंगफली किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और कृषि विज्ञान केंद्र, कपूरथला ने मोथावल गांव में एक "क्षेत्रीय अध्ययन और यात्रा संगोष्ठी" का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में किसानों को राज्य में भूमिगत जल संरक्षण में योगदान देने के लिए वसंत ऋतु में मूंगफली की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछले तीन वर्षों से मूंगफली की खेती कर रहे किसानों ने संगोष्ठी के दौरान अपने सफल अनुभव साझा किए। यह द्विवार्षिक फसल रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रखती है और मक्का की तुलना में इसमें पानी की खपत बहुत कम होती है। राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सेचेवाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब के भूजल संरक्षण और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फसल विविधता सबसे जरूरी है। श्री सेचेवाल ने याद दिलाया कि दोआबा क्षेत्र कभी मूंगफली की खेती के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि, मौसम में बदलाव, कम वर्षा और ट्यूबवेल के अत्यधिक उपयोग

के कारण मूंगफली की खेती में रुचि कम हो गई। ट्यूबवेल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल पर भी दबाव बढ़ गया है। जो पानी कभी 30 फुट की गहराई पर आसानी से मिल जाता था, अब वह 300 फुट की गहराई पर है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पंजाब के भूजल का संरक्षण तभी संभव है जब किसान अपनी पारंपरिक फसलों की ओर लौटें। श्री सेचेवाल ने मोथावल के प्रमुख किसान जरनैल सिंह की पहल की सराहना की, जिन्होंने तीन साल पहले मक्के के विकल्प के रूप में मूंगफली उगाना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि जरनैल सिंह के प्रयासों के कारण पंजाब ने एक बार फिर पारंपरिक फसलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस वर्ष, जरनैल सिंह ने 26 एकड़ भूमि पर मूंगफली बोई, जो अन्य किसानों के लिए एक उदाहरण है। इसके परिणामस्वरूप, जिले में मूंगफली की खेती का क्षेत्रफल तीन साल पहले मात्र 9 किलो बीज से बढ़कर आज 72 एकड़ हो गया है। लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल ने इसे एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि वसंत ऋतु में उगने वाली मूंगफली द्विवार्षिक फसल है और मिट्टी की सेहत बनाए रखने में सहायक होती है। इस फसल से प्रति एकड़ 25 से 28 क्विंटल प्रति वर्ष उपज प्राप्त होती है।

वर्षा खांगवाल को झज्जर का उपायुक्त नियुक्त होने पर उज्ज्वल भविष्य की कामना : केएम पांडुरंग

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खांगवाल के झज्जर के उपायुक्त पद पर नियुक्त होने के उपरांत आज विभाग की ओर से उनके सम्मान में एक गरिमामयी विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्रीमती वर्षा खांगवाल के कार्यकाल को याद करते हुए उनके प्रशासनिक कौशल, कार्य के प्रति समर्पण तथा सरल व्यवहार की सराहना की।

मीडिया वैलबीइंग एसोसिएशन ने शिमला में समारोह कर पत्रकारों वितरित कीं एक्सीडेंटल पॉलिसियां

चंडीगढ़। पत्रकारों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान को समर्पित मीडिया वैलबीइंग एसोसिएशन के हिमाचल प्रदेश प्रभारी एवं उत्तर भारत के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय भुटानी की पहल पर प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित एक्सीडेंटल इंशोरेंस पॉलिसी लॉन्चिंग एवं वितरण समारोह सोमवार को शिमला स्थित होलीडे होम में उत्साह और गरिमामय वातावरण के बीच संपन्न हुआ। समारोह में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह

में शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान प्रदेशभर के विभिन्न स्थानों से पत्रकारों ने शिरकत की और वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अश्विनी शर्मा, डॉ. शशि भूषण,अर्चना फुल, अनिल हेडली और जी आई पी आर सिंपल सकलानी सहित समाजसेवी गुरमीत सिंह अरोड़ा व बिमला ठाकुर को भी सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मौके पर मार्गदर्शन भी किया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को दस-दस लाख रुपए की नि:शुल्क एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसियां वितरित की गईं। समारोह में पत्रकारों के कल्याण, सुरक्षा, बीमा, पेंशन और बदलते मीडिया परिवेश में उनकी भूमिका को लेकर

विस्तृत चर्चा हुई। संगठन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी के स्वागत भाषण से शुरू हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संगठन के कार्यों की सराहना की और एसोसिएशन हिमाचल प्रभारी संजय भुटानी द्वारा मंच से रखे गए मांग पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन देने पर सहमत हैं व इस बारे घोषणा की जा सकती है। मांग पत्र में हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों को हरियाणा व अन्य राज्यों की तर्ज पर पेंशन देने, सचिवालय में प्रेस रूम की व्यवस्था करने, पत्रकारों को कैंशलेस हैल्थ मैडिकल की सुविधा देने और हिमाचल

प्रदेश वेब पॉलिसी के अनुसार संपादकों को एक्कीडेटेशन देने की बात रखी गई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एसोसिएशन ने पत्रकारों के कल्याण के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया है, वह देशभर के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यों को देखकर उन्हें यह महसूस हुआ कि नेताओं के लिए भी इसी प्रकार का कोई संगठन होना चाहिए, जो उनके सामाजिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती से पत्रकार कल्याण के लिए शुरू की गई इस मुहिम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की

मजबूती के लिए मीडिया का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि संगठन द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए जो कार्य शुरू किए गए हैं, वे दूरगामी सोच का परिचायक हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान शांतिप्रिय राज्य के रूप में है और यहां पत्रकारों तथा प्रशासन के बीच बेहतर संवाद और सहयोग का वातावरण रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सामने आज अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन योजनाओं

को लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार की प्राथमिकता पत्रकारों के हितों की रक्षा करना है। नरेश चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे कमजोर करने का कोई भी प्रयास उचित नहीं है। शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि देश में अब तक किसी पत्रकार संगठन ने पत्रकारों के कल्याण के लिए इतना व्यापक कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और ऐसे समय में मीडिया वैलबीइंग एसोसिएशन पत्रकारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पत्रकार

समाज और सरकार के बीच महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। उनकी निष्पक्ष रिपोर्टिंग से प्रशासन और जनप्रतिनिधि यों को वास्तविक स्थिति का पता चलता है, जिससे व्यवस्था में सुधार संभव होता है। उन्होंने संगठन के पदाधिाकारियों की सराहना करते हुए उनके प्रयासों को प्रेरणादायी बताया। मीडिया वैलबीइंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने संगठन की गतिविधिा्यों की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था पत्रकारों को टर्म इश्योरेंस, एक्सीडेंटल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी तथा उनके परिवारों के लिए कैंशलेस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद पत्रकारों

को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के बीच पत्रकारों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संगठन इसी उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहा है और भविष्य में देशभर में अपने दायरे का विस्तार करेगा। इस अवसर पर एसोसिएशन के हिमाचल प्रदेश प्रभारी संजय भुटानी ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आयोजित इस शानदार समारोह में आए अतिथियों एवं पत्रकारों का अभिनन्दन करते हुए कहा कि समय के साथ पत्रकारिता का रूप काफी बदल गया है



इंजीनियर अरबिंद मोहंती पर विजिलेंस का शिकंजा

भुवनेश्वर १६/१० (संवाददाता): विजिलेंस ने मयूरभंज जिले के बेतानोटी में रूरल वर्क्स सब-डिविजन के एंजीनियर अरबिंद मोहंती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। ताजा कार्रवाई में विजिलेंस अधिकारियों ने बालेश्वर स्थित एक कॉन्स्ट्रक्टर के घर से कथित तौर पर छिपाकर रखे गए 20 प्लॉट के जमीन संबंधी दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, ये दस्तावेज मोहंती से जुड़े बताए जा रहे हैं और अब उनकी खरीद, स्वामित्व तथा विजीय स्रोतों की जांच की जा रही है। विजिलेंस की जानकारी के मुताबिक, सोमवार को अरबिंद मोहंती से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। इस दौरान उनके आवास और अन्य संबंधित स्थानों से बड़ी संख्या में दस्तावेज, रिकॉर्ड और विजीय जानकारी बरामद की गई। जांच के दौरान एजेंसी को सूचना मिली कि कुछ अहम दस्तावेज एक कॉन्स्ट्रक्टर के घर पर छिपाकर रखे गए हैं। इसके बाद टीम ने बालेश्वर में संबंधित कॉन्स्ट्रक्टर के घर की तलाशी ली। आरोप है कि छापेमारी की भनक लगने के बाद कुछ दस्तावेजों को

जमीन में दबा दिया गया था। विजिलेंस अधिकारियों ने संदेह के आधार पर जमीन की खुदाई कराई, जिसके बाद वहां से 20 प्लॉट से जुड़े जमीन के कागजात बरामद हुए। इन दस्तावेजों की बरामदगी को जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन किसके नाम पर खरीदी गई थी, भुगतान किस माध्यम से हुआ और ज़्यादा इन संपत्तियों का वास्तविक लाभार्थी अरबिंद मोहंती थे। जांच के दौरान एक लॉकर का भी पता चला है। विजिलेंस का आरोप है कि यह लॉकर कथित तौर पर उसी कॉन्स्ट्रक्टर के नाम पर बेनामी तरीके से संचालित किया जा रहा था, जबकि उसमें रखी संपत्ति मोहंती से संबंधित थी। लॉकर खोले जाने पर उसमें से 2.77 लाख रुपये नकद और सोने के आभूषण बरामद किए गए। विजिलेंस ने नकदी और सोने को जप्त कर लिया है। अब सोने का वजन, बाजार मूल्य और उसकी खरीद से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। एजेंसी का कहना है कि सोमवार को मोहंती से संबंधित कुल 10 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी।

इन ठिकानों में उनके आवास, रिश्तेदारों या परिचितों से जुड़े स्थान और अन्य संभावित संपत्ति स्थल शामिल थे। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में विजिलेंस की जांच आमतौर पर संबंधित अधिकारी की कुल वैध आय और उसके नाम या नियंत्रण में मौजूद संपत्तियों की तुलना के आधार पर आगे बढ़ती है। यदि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति पाई जाती है और उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तो मामला गंभीर माना जाता है। मोहंती पर भी आरोप है कि उनके पास उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति है। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर विजिलेंस उनकी कुल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। मकान खोजें 20 प्लॉट के दस्तावेज मिलने के बाद जांच का फोकस भूमि निवेश पर भी केंद्रित हो गया है। एजेंसी यह देख रही है कि ये प्लॉट कब खरीदे गए, किस नाम से रजिस्ट्री हुई और किस खाते से भुगतान किया गया। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि ज़्यादा संपत्तियों की खरीद में किसी कॉन्स्ट्रक्टर, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल बेनामी स्वामित्व

के लिए किया गया। यदि ऐसा पाया जाता है तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। कॉन्स्ट्रक्टर के घर से दस्तावेज मिलने के कारण विजिलेंस उसके विजीय और कारोबारी संबंधों की भी पड़ताल कर सकती है। यह देखा जाएगा कि संबंधित कॉन्स्ट्रक्टर और मोहंती के बीच विभागीय या निजी स्तर पर किस तरह के संबंध थे। रूरल वर्क्स विभाग से जुड़े एंजीनियर अरबिंद मोहंती के पद पर रहते हुए मोहंती के पास विभिन्न निर्माण और विकास परियोजनाओं से संबंधित जिम्मेदारियां थीं। ऐसे में विजिलेंस यह भी जांच सकती है कि ज़्यादा किसी ठेकेदार या निर्माण एजेंसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले आर्थिक फायदा लिया गया। हालांकि इस संबंध में अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है और मामले की जांच जारी है। विजिलेंस की ओर से अब तक बरामद दस्तावेज और संपत्तियां प्राथमिक जांच का हिस्सा हैं। जमीन में दबाकर रखे गए दस्तावेज मिलने का दावा इस मामले को और गंभीर बनाता है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दस्तावेज कब और किसके

निर्देश पर छिपाए गए थे। इसके लिए कॉन्स्ट्रक्टर और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा सकती है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और डिजिटल डेटा की भी जांच होने की संभावना है। लॉकर से मिली नकदी और सोने के मामले में भी स्वामित्व की पुष्टि की जाएगी। यदि यह साबित होता है कि संपत्ति वास्तव में मोहंती की थी लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रखी गई थी, तो उनके खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। विजिलेंस विभाग ने इस मामले में पहले ही मोहंती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब नए दस्तावेज और बरामदगी सामने आने से जांच में और अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। मकान खोजें फिलहाल अधिकारियों का पूरा ध्यान मोहंती की कुल संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश, जमीन और अन्य परिसंपत्तियों का मिलान उनकी वैध आय से करने पर है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित आय से अधिक संपत्ति का वास्तविक अनुपात कितना है और इसमें अन्य लोगों की भूमिका ज़्यादा रही।

आरएसपी ने परिधीय गांवों के 20 लोगों को मशरूम की खेती का दिया प्रशिक्षण



राउरकेला १६/१० (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सीएसआर विभाग द्वारा कौशल विकास एवं आजीविका सृजन की पहल के तहत बिसरा प्रखंड के जरेइकेला तथा लाठीकटा प्रखंड के बदलकी गांव के 20 प्रतिभागियों के लिए मशरूम की खेती पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 6 एवं 7 अक्टूबर 2026 को राउरकेला स्थित इंस्टीट्यूट फॉर पेरिफेरल डेवलपमेंट (आईपी डी) में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मशरूम की जैविकी,

उत्पादन के लिए आधार सामग्री (सब्सट्रेट) तैयार करने एवं उसके निर्जीवीकरण, अनुकूल वातावरण के प्रबंधन, कटाई के बाद की प्रक्रियाओं तथा मशरूम उत्पादन के अर्थशास्त्र एवं विपणन सहित खेती की विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम का समापन प्रमाणपत्र वितरण समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री बिभाबसु मलिक ने प्रतिभागियों को संबोधित किया, जबकि

महाप्रबंधक (नगर सेवाएं), श्री प्रदीप कुमार साहू विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लाभार्थियों ने भी प्रशिक्षण से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उप महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री आर. बी. बारा ने स्वागत भाषण दिया तथा उप प्रबंधक (सीएसआर), श्री एस. के. शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रमाणित मशरूम खेती प्रशिक्षक सुश्री कमला टोप्पो तथा एनआईटी राउरकेला के सलाहकार श्री गोकुल मिंज ने किया। कार्यक्रम का समन्वय अनुभाग अधिकारी (सीएस आर), श्री बेनेडिक्ट एक्का ने किया।

नकली दवाएं, नकली चिकित्सा उपकरण जप्त किए

केंद्रपाड़ा १६/१० (संवाददाता): ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को केंद्रपाड़ा शहर के सुनेलो इलाके में एक बिना लाइसेंस वाले दवा वितरक को गिरफ्तार किया और उसके गोदाम से 10 लाख रुपये कीमत की नकली नशीली दवाएं, घटिया दवाएं और नकली मेडिकल डिवाइस जप्त किए। नकली दवाओं का यह रैकट मंगलवार को तब सामने आया जब अधिकारियों ने आरोपी प्रहजुन लेंका (39) के किराए के गोदाम पर छापा मारा। यह छापा मंगलवार सुबह से



रात तक चला। कटक सर्कल-डू के असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर धर्मदेव पुहान ने कहा, जप्त की गई दवाओं में हर्ज़न दवाएं पेंटाज़ोसिन और ट्रामाडोल, और इन्ज़र दवा केटामाइन शामिल हैं। छापे के दौरान हमने पहली

बार 7 लाख रुपये कीमत के नकली मेडिकल डिवाइस भी जप्त किए। अधिकारियों को शक है कि यह नेटवर्क जिले और आस-पास के इलाकों के कई अस्पतालों और जलीनिकों को नकली दवाएं, जीवन रक्षक

दवाएं, इंजेक्शन और मेडिकल डिवाइस सप्लाई करता था और कथित तौर पर उन्हें लगभग 50 प्रतिशत की छूट पर देता था। पुहान ने कहा, इन नकली दवाओं में सक्रिय औषधीय तत्व नहीं होते हैं और इनमें हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। खरीदारों को धोखा देने और ज़्यादा से ज़्यादा गैर-कानूनी मुनाफा कमाने के लिए, नकली लेबल पर त्रुटिपूर्ण लगाए गए थे जो स्कैन करने पर काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि लेंका पिछले चार सालों से सुनेलो में किराए के घर से यह गैर-कानूनी धंधा चला रहा था।

तारातारिणी मंदिर की हुंडी में मिले दो बच्चों के

पुरुषोत्तमपुर १६/१० (संवाददाता): गंजाम जिले की मुख्य देवी, माँ तारातारिणी मंदिर में दान पेटी (हुंडी) खोलने के दौरान बच्चों के लिखे दो भावुक पत्र मिले। पता चला कि दान पेटियों से सोने-चाँदी के गहने, विदेशी मुद्रा और कुल 25,91,743 रुपये नकद मिले। इनमें से एक पत्र ओडिशा में और दूसरा अंग्रेज़ी में लिखा गया था।



इन दिल को छू लेने वाली प्रार्थनाओं ने मंदिर में मौजूद भक्तों का मन मोह लिया। एक पत्र में, एक छोटे लड़के ने अपने परिवार की मुश्किलों का जिक्र किया और माँ तारातारिणी से प्रार्थना की कि वह उसे और उसकी माँ को मुश्किल समय से उबरने में मदद करें। उसने

कि वे हमेशा उसके परिवार के साथ रहें और उनका मार्गदर्शन करें।

उसने अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की कामना की, और एक अच्छा इंसान बनने और सच्चाई के रास्ते पर चलने की शक्ति माँगी। उसने देवी से अपनी गलतियों के

भावनात्मक पत्र

लिए माफ़ी भी माँगी और खुद व अपने परिवार के लिए शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद माँगा। हुंडी में चढ़ाए गए दान की गिनती के दौरान नकद और सोने-चाँदी के गहनों के बीच ये पत्र मिले। हुंडी को मंदिर के कार्यकारी अधिकारी और पुरुषोत्तमपुर के तहसीलदार बिनोद कुमार बेहरा की देखरेख में, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खोला गया। सफेद कागज़ पर नीली स्याही से लिखी इन सरल और मासूम प्रार्थनाओं ने सबका ध्यान खींचा और वहाँ मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। ये पत्र भक्तों और देवी के बीच गहरे जुड़ाव को दर्शाते थे।

बीजेडी ने नई दिल्ली में विपक्ष के मार्च में शामिल होकर मांग की



भुवनेश्वर १६/१० (संवाददाता): बीजू जनता दल (बीजेडी) ने मंगलवार को नई दिल्ली में इंडिया ज़्लॉक के सांसदों के विरोध मार्च में भाग लिया, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और देश भर में 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने के संबंध में उनके कथित मनमाने कार्यों पर मुज्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। वोटर गाइड देखें बीजद संसदीय दल के नेता मानस मंगराज ने कहा

कि पार्टी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक के निर्देशानुसार पार्टी के सांसद विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पटनायक पहले ही एसआईआर अज़्यास में कुमार की कथित भूमिका को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं।

बीजद की समान दूरी की नीति को कमजोर करने पर भाजपा की आलोचना का जवाब देते हुए, मंगराज ने कहा कि पार्टी ने इंडिया ज़्लॉक और एनडीए दोनों से समान दूरी

बनाए रखी है। हालाँकि, लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में, बीजद ने मंगलवार के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। मंगराज ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर ओडिशा में 20 लाख से अधिक और देश भर में 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं को बाहर करने से गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि धामनार की घटना ने इन आशंकाओं को और बढ़ा दिया है।

आरएसपी में ठेका श्रमिकों के बीच सुरक्षा संस्कृति को और सुदृढ़ करने के लिए 'सुरक्षा चर्चा' का शुभारंभ

राउरकेला १६/१० (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) ने ठेका श्रमिकों के बीच सुरक्षा जागरूकता एवं सहभागिता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में एक नई सुरक्षा पहल 'सुरक्षा चर्चा' का शुभारंभ किया। अपनों से अपनों की बात, सुरक्षा के लिए विषयवस्तु पर आधारित इस कार्यक्रम ने श्रमिकों को सुरक्षा संबंधी चिंताओं को खुलकर साझा करने, असुरक्षित परिस्थितियों की जानकारी देने तथा कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करने हेतु एक सुव्यवस्थित मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), श्री बी.आर.पलाई ने कहा कि ठेका श्रमिक आर.एस.पी. के परिचालन का अभिन्न अंग हैं तथा उनकी



सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रबंधन, पर्यवेक्षकों, ठेकेदारों और श्रमिकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा की कीमत पर कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से सुरक्षा जागरूकता को सुरक्षित व्यवहार में परिणत करने तथा यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि प्रत्येक श्रमिक दिन के अंत में सुरक्षित अपने घर लौटे। इससे पूर्व, मुख्य महा

प्रबंधक प्रभारी (सेवा), श्री अतिश चंद्र सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा निकट-दुर्घटना की घटनाओं और असुरक्षित परिस्थितियों से सीख लेने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी संबंधितों से कार्यक्रम के दौरान हुई चर्चाओं को कार्यस्थल की सुरक्षा में ठोस सुधार के रूप में परिणत करने का आह्वान किया।

इस पहल में मुख्य महा प्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्नि

शमन सेवा), श्री हीरालाल महापात्र, महा प्रबंधक (सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग), श्री अबकास बेहेरा, वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय सुरक्षा अधिकारी (डी.एस.ओ.), सहायक सुरक्षा अधिकारी (ए.एस.ओ.) तथा विभिन्न विभागों के लगभग 100 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर 'ऊंचाई पर कार्य' विषय पर एक तकनीकी प्रस्तुतिकरण दी गई।

एस.एम.एस.-2, सी.पी.-2 तथा टी. एंड आर.एम. के विभागीय सुरक्षा अधिकारियों ने सहायक महा प्रबंधक (एस.ई.डी.), श्री बी.के.पाढ़ी के साथ विभिन्न दुर्घटनाओं एवं निकट-दुर्घटना की घटनाओं से प्राप्त सीख साझा की। विचार-विमर्श सत्र के दौरान ठेका श्रमिकों को कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार के लिए अपने अनुभव, चिंताएं और सुझाव साझा करने का अवसर मिला। उल्लेखनीय है कि अधिकाधिक ठेका श्रमिकों को इस पहल से जोड़ने के उद्देश्य से 'सुरक्षा चर्चा' का आयोजन प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाएगा। कार्यक्रम के प्राथम मं श्री अबकास बेहेरा ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया। वरिष्ठ प्रबंधक (एस.ई.डी.), श्री सौज्य रंजन बिस्वाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि उप प्रबंधक (एस.ई.डी.), श्री नीलकंठ सेठी ने कार्यक्रम का संचालन किया।